



सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से मिलेगी सस्ती बिजली

स्थिर और मजबूत सरकार की झलक उसके बजट में भी दिखाई देती है। बजट को विकास का योगी मॉडल कहा जा सकता है। आंकड़ों पर न भी जाएं तो भी इसके प्रमाण के रूप में मुख्य रूप से चार बातें कही जा सकती हैं। हर साल प्रदेश के बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। भारत में आकार के हिसाब से यह सबसे बड़ा बजट है। दूसरी प्रमुख बात बजट में पूंजीगत व्यय का बढ़ना है। इस बार पूंजीगत व्यय 26 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। पिछली बार यह दर 24 फीसदी था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आने वाले निवेश इसी का परिणाम हैं। तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होना है।



सरकार ने इस बार भी अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी जारी रखी है। सड़क निर्माण और दो लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण इसी के तहत हैं। जेवर एयरपोर्ट रनवे की पट्टी दो से पांच की गई हैं। यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रही है बल्कि भविष्य के हिसाब से उनका आंकलन करते हुए भी चल रही है। इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर सस्ती बिजली तथा पर्यावरण मित्रवत ऊर्जा की दिशा में भी आगे बढ़ने का काम इस बजट से होगा। चौथी प्रमुख बात कृषि क्षेत्र के लिए है। बजट में प्रयास किया गया है कि उत्पादन लागत को कम से कम करते हुए उपज को बढ़ाया जाए। इसके तहत सौर नलकूप, कृषि नलकूपों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह बजट एक तरफ प्रकृति और पर्यावरण को बढ़ावा देगा तो दूसरी ओर विकास के हाईवे पर रफ्तार पकड़ता भी दिखाई दे रहा है।

—**प्रो. मनोज अग्रवाल, विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय**

लविवि : नकल करते तीन छात्र पकड़े गए

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान बुधवार को तीन छात्र नकल करते पकड़े गए। तीनों ही छात्र नवीन कैम्पस में परीक्षा दे रहे थे। (माई सिटी रिपोर्टर)

अवसाद से बचने में माइंड फुलनेस अहम

लखनऊ। लविवि के समाज कार्य विभाग में यूथ काउंसिलिंग हेल्थ सेंटर की ओर से मानसिक स्वास्थ्य व जीवन कौशल कार्यशाला हुई। बलरामपुर अस्पताल से क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट गरिमा सिंह ने अवसाद की समस्या से निपटने के लिए छात्र-छात्राओं को माइंड फुलनेस का प्रशिक्षण दिया गया। यूथ काउंसिलिंग सेंटर के नोडल व मुख्य कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी, प्रो. रूपेश कुमार, डॉ. मोहिनी गौतम मौजूद रहे। (संवाद)

बजट योगी के विकास मॉडल की स्पष्ट झलक

वरिष्ठ संवाददाता (VOL)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. एमके अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश किये गये बजट को लेकर कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में योगी विकास मॉडल की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। यह बजट उत्तर प्रदेश के तीन विकास को बढ़ावा हुआ नजर आता है। जहां वित्तीय व्यूह रचना के कारण उत्तर प्रदेश उत्पादन के नए स्रोत	लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. एमके अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश किये गये बजट को लेकर कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में योगी विकास मॉडल की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। यह बजट उत्तर प्रदेश के तीन विकास को बढ़ावा हुआ नजर आता है। जहां वित्तीय व्यूह रचना के कारण उत्तर प्रदेश उत्पादन के नए स्रोत
---	---

● बजट प्रतिक्रिया

सृजित करता हुआ प्रतीत होता है जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश कई मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह बजट जहां अवस्थापना सुविधा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर और ज्यादा जोर दे रहा है। वहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष प्रयास काफी महत्वपूर्ण है। तापीय विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास दिख रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आज

निर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। सड़क निर्माण तथा एयरपोर्ट में तीव्र विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश अब निवेश का उत्तम गंतव्य बन चुका है, यह बजट इस तथ्य को पुनः रेखांकित करता है।



कृषि के क्षेत्र में उत्पादन-उत्पादकता तथा कुशलता बढ़ाने के व्यापक प्रयास दृष्टिगत होते हैं। यह चाहे नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था हो या सोलर पंप की बात हो या कृषि उत्पादन तथा उसके विपणन की बात हो औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन बढ़ाने के भी कई प्रयास दिखाई पड़ते हैं। इस क्रम में

एमएसएमई तथा स्टार्टअप आदि पर जोर दिया गया है। इन सब में दूरिग विकास, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा, युवाओं तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रयास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नयी गति प्रदान करेंगे।

योगी सरकार का यह बजट ऐसे समय में आया है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ गयी है। ऐसे में योगी मॉडल का बजट प्रयास प्रयास तथा निजी निवेश मिलकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नयी ऊर्जा तथा गति प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश अपने एक ट्रिलियन डॉलर के निजी निवेश को हासिल कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेश किये गये बजट में शिक्षा के प्रति गंभीरता दिखायी है। यह सरकार के बजट में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। इसमें युवाओं को प्रोत्साहित और नए नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था बजट रखा है। निश्चित तौर पर इससे प्रदेश के युवाओं के विकास को पंख लगेंगे और प्रदेश के युवाओं का समावेशी विकास होगा और युवाओं को रोजगार की कमी नहीं होगी।



योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में योगी विकास मॉडल की स्पष्ट झलक देखने को मिली है। यह बजट उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास को बढ़ाता हुआ

नजर आता है, जहां वित्तीय व्यूह रचना के कारण उत्तर प्रदेश उत्पादन के नए स्रोत सृजित करता हुआ प्रतीत होता है। जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही प्रदेश कई मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर से बढ़ता दिख रहा है। 2023-24 का बजट जहां अवस्थापना सुविधा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर और ज्यादा जोर दे रहा है वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष प्रयास काफी महत्वपूर्ण हैं। विद्युत उत्पादन में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के कारण प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर हो रहा है। — प्रोफेसर एमके अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय

बजट: योगी विकास मॉडल की स्पष्ट झलक

● बजट ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निधि निवेश में तीव्र वृद्धि की संभावना बढ़ गयी है



लखनऊ। योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में योगी विकास मॉडल की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। यह बजट उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास को बढ़ाता हुआ नजर आता है। जहां वित्तीय व्यूह रचना के कारण उत्तर प्रदेश उत्पादन के नए स्रोत सृजित करता हुआ प्रतीत होता है जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। वहीं उत्तर प्रदेश कई मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

2023-24 का यह बजट जहां अवस्थापना सुविधा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर और ज्यादा जोर दे रहा है, वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष प्रयास काफी महत्वपूर्ण है। तापीय विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास दिख रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। सड़क तथा एयरपोर्ट के तीव्र निर्माण विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश अब निवेश का उत्तम गंतव्य बन चुका है। यह बजट इस तथ्य को पुनः रेखांकित करता है। कृषि सेल में उत्पादन उत्पादकता तथा कुशलता बढ़ाने के व्यापक प्रयास दृष्टिगत होते हैं। यह नलकूपों

के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था है या सोलर पंप की बात हो या कृषि उत्पादन तथा चाहे हो उसके विपणन की बात हो, औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन बढ़ाने के भी कई प्रयास दिखायी पड़ते हैं। इस क्रम में एमएसएमई तथा स्टार्टअप आदि पर जोर शामिल है। इन सब में दूरिग विकास, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा युवाओं तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रयास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नयी गति प्रदान करेंगे। यह योगी सरकार का यह बजट ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निधि निवेश में तीव्र वृद्धि की संभावना बढ़ गयी है। ऐसे में बहुत योगी मॉडल का बजट प्रयास तथा निजी निवेश मिलकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा तथा गति प्रदान कर सकेंगे। यह इस प्रकार उत्तर प्रदेश अपने एक ट्रिलियन डॉलर के निजी निवेश को हासिल कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।

(लेखक- प्रो. मनोज अग्रवाल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं)

छात्र-छात्राओं को दी मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में संचालित यूथ काउंसिलिंग हेल्थ सेंटर की ओर से आयोजित मानसिक स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान बलरामपुर अस्पताल से आई हुए क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट गरिमा सिंह ने छात्र छात्राओं से उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को जानकर उनसे उचित निपटान के तरीकों को बताया। विशेषज्ञ गरिमा

लखनऊ में भी मिलने लगेंगी दिल्ली हाट जैसी सुविधाएं

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इससे निश्चित ही पूंजीगत व्यय 26 फीसद होगा। प्रदेश के इस बजट से लखनऊ की अर्थव्यवस्था भी कई मायनों में प्रभावित होती दिख रही है। विशेष कर स्वास्थ्य, पुलिस, कानून व्यवस्था, आइटी और परंपरागत करीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए बजट में सीधे प्रविधान है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बजट के माध्यम से अर्थशास्त्री, लवि



का सीधा असर यहां पड़ेगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में 558 बेड का इमरजेंसी मेडिसिन और रीजनल लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर और एडवांस डायलिटिक सेंटर की स्थापना का भी प्रविधान किया गया है। इसी तरह से किंग जार्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट में डायलिटिक रेडिओथेपी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर को स्थापित करने लिए बजट में व्यवस्था हुई है। लखनऊ मेडिकल केयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। रीजनल ट्रांसप्लांट सेंटर और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि ऐसा सेंटर देश के अन्य क्षेत्रों में बहुत कम है। हरदोई रोड पर लखनऊ

कानून व्यवस्था होगी मजबूत

पुलिस और कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में एडवांस डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। इससे लखनऊ डिविजन स्तर पर भी फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। बजट में राज्य टेक्सटाइल व गारमेंट नीति का जिक्र किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सीड फंड देने की बात की गई है। लखनऊ में नेशनल टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने से इसका लाभ राजधानी को भी मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बजट में युनिटी माल को स्थापित करने के लिए 200 करोड़ का प्रविधान है। इससे प्रदेश के सभी जिलों के उत्पादों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित और बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। लखनऊ में भी दिल्ली हाट जैसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। टाटा टेक्नोलाजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर का तकनीकी उत्थान कर रही है। (लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं।)

लवि के सात छात्र-छात्राओं को मिली नौकरी

लखनऊ विश्वविद्यालय की सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की ओर से सात छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। सेल की डायरेक्टर प्रो. मधुरिमा लाल ने बताया कि आदित्य बिरला कंपनी में एमबीए के अंकित राज, विशाल सिंह, रोशनी गौतम, बीटेक के अभिनव आदित्य, बीकाम की भव्या सक्सेना, एमकाम से मोहित अग्रवाल और एमकाम एप्लाइड इकोनामिक्स से माधवी यादव शामिल हैं। इन सभी को साढ़े तीन लाख रुपये सालाना पैकेज मिलेगा।

स्नातक पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की शुरुआत गुरुवार से होगी। पहले दिन बीए, बीकाम, बीकाम आनर्स, बीबीए, बीबीए आइबी व बीबीए एमएस पांचवें सेमेस्टर के विभिन्न विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार से शुरू होने वाली स्नातक पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं में करीब 50 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। (जासं)

सात छात्रों को मिला प्लेसमेंट

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने फिर से सात छात्रों का प्लेसमेंट करवाया। इस बार जानी मानी कम्पनी आदित्य बिरला ने तीन छात्र व्यापार प्रशासन विभाग से एक बीटेक एक बीकॉम एवं एक एम काम और एक अप्लाइड एकांमिक्स से चयन किया। इन सभी को इग्जेक्यूटिव रेलेशनशिप मैनेजर के पद पर रु 3.5 लाख के सालाना पैकेज पर नियुक्त किया है। अंकित राज, विशाल सिंह

और रोशनी गौतम व्यापार प्रशासन विभाग से, अभिनव आदित्य बी टेक से, भव्या सक्सेना बी कॉम, मोहित अग्रवाल एम काम और माधवी यादव एम काम व्यवहारिक अर्थशास्त्र से चयनित हुए।